



## प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण घरेलू बीमाकर्त्ता

### प्रलिस के लिये

'प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण घरेलू बीमाकर्त्ता, अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ

### मेन्स के लिये:

बीमा क्षेत्र में सार्वजनिक कंपनियों की भूमिका, बीमा क्षेत्र में स्थिरता हेतु सरकार के प्रयास

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'भारतीय बीमा वनियामक और विकास प्राधिकरण' (Insurance Regulatory and Development Authority of India- IRDAI) द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की तीन बीमा कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये 'प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण घरेलू बीमाकर्त्ता' (Domestic Systemically Important Insurers or D-SIIs) के तौर पर चिह्नित किया गया है।

## प्रमुख बिंदु:

- IRDAI द्वारा भारतीय जीवन बीमा नगिम (Life Insurance Corporation of India- LIC), भारतीय साधारण बीमा नगिम (General Insurance Corporation of India) और न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये D-SIIs के रूप में चिह्नित किया गया है।
- D-SIIs को ऐसे बीमाकर्त्ताओं के रूप में देखा जाता है, जो 'टू बगि ऑर टू इंपोर्टेंट टू फेल' (Too Big or Too Important to Fail- TBTF) के सिद्धांत पर कार्य करते हैं।
- D-SIIs ऐसे आकार और बाजार महत्त्व, घरेलू तथा वैश्विक परस्पर संबंध के बीमाकर्त्ताओं को संदर्भित करता है, जिनका संकट या वफिलता घरेलू वित्तीय प्रणाली में एक बड़ी अव्यवस्था का कारण बन सकता है।
- अतः राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बीमा सेवाओं की निरबाध उपलब्धता के लिये निरंतर D-SIIs का कार्य करना आवश्यक है।
- गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में [भारतीय रिजर्व बैंक](#) (Reserve Bank of India- RBI) द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (SBI), आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) और एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) को 'प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण घरेलू बैंक' ( Domestic Systemically Important Banks or D-SIB) के तौर पर चिह्नित किया गया था।
- RBI के मानदंडों के अनुसार, D-SIB के रूप में चिह्नित बैंकों को अपने निरंतर संचालन के लिये [पूंजी संरक्षण बफर](#) के रूप (Capital Conservation Buffer) में अधिक पूंजी अलग रखनी होती है।

## कारण:

- D-SIIs के साथ जुड़ी हुई TBTF की अवधारणा और सरकार के समर्थन से जुड़ी अपेक्षाएँ ऐसी इकाइयों की जोखिम लेने की भावना में वृद्धि, बाजार में अनुशासन की कमी तथा प्रतिस्पर्धी विकृतियों पैदा कर सकती हैं जिससे भविष्य में इनमें संकट की संभावनाएँ भी बढ़ सकती हैं।
- IRDAI के अनुसार, पिछले 15 वर्षों में देश के बीमा क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है, इसके साथ ही कुछ बीमाकर्त्ताओं का बाजार के एक बड़े हिस्से पर हस्तक्षेप है और वे अन्य वित्तीय संस्थानों से भी जुड़े हैं। ऐसे में इनकी असफलता अर्थव्यवस्था के लिये एक बड़ी चुनौती बन सकती है।
- इन चिंताओं को देखते हुए IRDAI द्वारा D-SIIs को प्रणालीगत जोखिमों (Systemic Risks) और नैतिक खतरे (Moral Hazard) के मुद्दों से निपटने के लिये अतिरिक्त नियामकीय उपायों के अधीन किये जाने का सुझाव दिया गया है।
- गौरतलब है कि बीमा क्षेत्र से जुड़ी चिंताओं को देखते जनवरी 2019 में IRDAI द्वारा D-SIIs पर एक समिति का गठन किया गया था।
- इससे पहले 'अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ' (International Association of Insurance Supervisors- IAIS) द्वारा सभी सदस्य देशों को स्थानीय/घरेलू D-SIIs के वनियामन हेतु एक नियामकीय ढाँचा तैयार करने के लिये कहा गया था।

## प्रभाव:

- IRDAI का यह नरिणय ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार द्वारा अगले वर्ष LIC के शेयरों को 'आरंभिक सार्वजनिक नरिगम' (Initial Public Offer-IPO) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने पर वचिर कया जा रहा है।
- सार्वजनिक क्षेत्र की इन तीन बीमा कंपनयों को D-SIIs के रूप में चहिनति करने से इनमें पारदर्शति बढ़ेगी और इनकी कार्यप्रणाली में भी सुधार होगा।
- IRDAI के अनुसार, इन तीन बीमाकर्त्ताओं को अपने कॉर्पोरेट प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के लयि कहा गया है।
- इसके साथ ही इनमें सभी प्रासंगिक जोखमिों की पहचान करने और एक प्रभावी जोखमि प्रबंधन प्रणाली को बढ़ावा देने का नरिदेश दया गया है।

## D-SIIs में स्थरिता सुनश्चिति करने के प्रयास:

- IRDAI द्वारा D-SIIs की पहचान और उनके पर्यवेक्षक के लयि एक पद्धतिका वकिस कया गया है।
- इसमें संचालन का आकार (कुल राजस्व के संदर्भ में), प्रबंधन के तहत संपत्तिका मूल्य, एक से अधिक क्षेत्राधिकार में वैश्विक गतविधियीं आदि मापदंडों को शामिल कया गया है।
- IRDAI द्वारा वार्षिक आधार पर D-SIIs की पहचान कर ऐसे बीमाकर्त्ताओं के नामों को सार्वजनिक कया जाएगा।

## ‘भारतीय बीमा वनियामक और वकिस प्राधिकरण’

### (Insurance Regulatory and Development Authority of India- IRDAI):

- IRDAI की स्थापना वर्ष 1999 में आर.एन. मल्होत्रा समतिका सफारशीं के आधार पर एक स्वायत्त नकाय के रूप में की गई थी।
- अप्रैल 2000 में इसे एक वैधानिक नकाय का दर्जा प्रदान कया गया।
- इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थति है।
- IRDAI का मुख्य उद्देश्य पॉलिसीधारकों के हतियों और अधिकारों की रक्षा तथा बीमा उद्योग के वकिस को बढ़ावा देना है।

## ‘अंतर्राष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ’

### (International Association of Insurance Supervisors- IAIS):

- IAIS बीमा पर्यवेक्षकों और नयामकों का एक स्वैच्छिक सदस्यता संगठन है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी।
- यह बीमा क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय मानक नरिधारण नकाय है, जो बीमा क्षेत्र के पर्यवेक्षण हेतु मानकों और सदिधांतों के नरिधारण और करयान्वयन में सहायता प्रदान करता है।

## स्रोत: द हट्टि